उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
मुख्यमंत्री आवास, न्यू कैंट रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 13 नवम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–04(11/49)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु के जन्मदिवस पर उनका स्मरण करते हुए, बाल दिवस की बच्चों को शुभकामनाएँ दी है। उनका बच्चों के प्रति अपार स्नेह था और उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा की बच्चे किसी भी समाज और राष्ट्र का भविष्य होते हैं और उनको उचित पालन पोषण और शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 13 नवम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–03(11/48)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हर राज्य की परिस्थिति के अनुरूप योजनाओं का निर्माण किया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सरकार पर्यटन तथा आर्गेनिक कृषि व हार्टीकल्चर आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने की पक्षधर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में ऊंचाई पर बसे ग्रामों हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रोपवे का प्रावधान भी जोड़ा जाये ताकि सडक निर्माण में पहाड़ों की क्षति न हो और इस योजना को प्रधानमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तौर पर जाना जाये।

उपाध्यक्ष नीति आयोग श्री राजीव कुमार ने कहा कि नीति आयोग और राज्य सरकार के बीच सीधा संबन्ध जरूरी है। वे राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को जानने के लिये आये हैं। यदि केन्द्र सरकार के स्तर से राज्य सरकार की किसी परियोजना में कोई सहायता करनी हो तो इसके लिये भी नीति आयोग कदम उठायेगा। राज्य सरकार की ओर से सचिव नियोजन श्री अमित नेगी ने राज्य के प्रमुख मुद्दों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण दिया। राज्य सरकार ने नीति आयोग के समक्ष विभिन्न क्षेत्रों हेतु परामर्शीय विशेषज्ञ सेवाओं की मांग भी की। इसमें विभागों के एकीकरण, राज्य योजनाओं के युक्तिसंगतीकरण, सॉलिड–वेस्ट मैनेजमेंट, नये पर्यटक स्थल, होम स्टे, पर्वतीय औद्योगिक नीति तथा रोपवे स्थापना के विषय प्रमुख हैं।

बैठक में वन भूमि हस्तांतरण के कारण परियोजनाओं में होने वाले विलंब पर भी चर्चा हुई। वन सचिव श्री अरविंद सिंह हयांकी ने कहा कि केन्द्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण में शिथिलता प्रदान की जाती है। इसी तर्ज पर राज्य की परियोजनाओं हेतु भी छूट प्रदान की जानी चाहिए। सामान्य अवस्था में 01 हेक्टेयर तक तथा आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में 05 हेक्टेयर तक वन भूमि हस्तान्तरण का राज्य को अधिकार प्राप्त था, जो कि नवम्बर 2016 में समाप्त हो गया। इसकी समय सीमा बढ़ाया जाना औचित्य पूर्ण होगा।

नीति आयोग से पर्यावरणीय सेवाओं के सापेक्ष ग्रीन बोनस प्रदान करने की मांग भी की गई। सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने बताया कि पर्यावरणीय कारणों से राज्य की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता का 20 प्रतिशत उपयोग भी नही हो पा रहा है। इससे लगभग चालीस हजार करोड़ का निवेश प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों द्वारा ईको सेंस्टिव जोन, आपदा प्रभावित 398 ग्रामों के विस्थापना, राज्य की गौचर, नैनी सैनी व चिन्यालीसौड हवाई पट्टियों को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत जाड़ेने की बात भी उठाई गई।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में रूचि व्यक्त की गई। सचिव शहरी विकास द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे 31 अक्टूबर को समाप्त हुआ है तथा लगभग एक लाख पांच हजार परिवार चिन्हित कर लिये गये है। इस योजना में बैंकों की सक्रियता बढ़ाने के लिये उनके लिये लक्ष्य भी निर्धारित किया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पंवार, श्री आनंद बर्द्धन सहित सभी सचिव उपस्थित थे।

देहरादून 13 नवम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(11/47)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सोमवार को हिमालयन इंस्टिट्यूट के संस्थापक डॉ.स्वामी राम की 22वीं पुण्यतिथी के अवसर पर आयोजित आराधना एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम डॉ.स्वामी राम जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत द्वारा हिमालयन इंस्टीट्यूट की लैब व रिसर्च बिल्डिंग एवं शौर्य दीवार का लोकार्पण किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कार्यक्रम में सम्मिलित होकर और यहां के आध्यात्मिक वातावरण को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। संस्थान द्वारा सेवा करने वालों एवं अपने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाना प्रशंसनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा 'सेवा रूरल' संस्था को सम्मानित किया जाना, एक अच्छा उदाहरण है। सेवा रूरल संस्थान द्वारा आदिवासियों के लिए किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में आदिवासी ज्यादा एडवाँस हैं, लेकिन अन्य राज्यों में आदिवासी आज भी जंगलों में कन्दमूल खाकर जीवनयापन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करा रही हैं। इसके लिए राज्य में टेली रेडियोलॉजी की शुरूवात कर दी गयी है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी डॉक्टर्स भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी स्वास्थ्य सुविधाएँ दुरूस्त करने को प्रतिबद्ध है।

सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हिमालय पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। राज्य में हिमालयन इंस्टीट्यूट स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। उन्होंने कहा कि हमें अपने युवाओं के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है।

इस अवसर पर कुलपति, हिमालयन इंस्टिट्यूट श्री विजय धस्माना एवं मैनेजिंग ट्रस्टी, सेवा रूरल संस्था, डॉ पंकज शाह उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 13 नवम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(11/46)

राज्य के युवाओं को सैन्य बलों की भर्ती परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये राज्य सरकार कुमाऊं और गढ़वाल में दो प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करेगी। यह निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और सेना के बैगलोर सिलेक्शन सेंटर के कमाण्डेंट मे.ज. वी.पी.एस. भाकुनी की मुलाकात के दौरान लिया गया। मे.ज. भाकुनी ने मुख्यमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण दिया जिसमें बताया गया कि वर्तमान में एनडीए और सीडीएस परीक्षाओं की सफलता दर आईएएस परीक्षा से भी कम है। सिविल सेवाओं के मुकाबले लगभग डेढ़ गुना अधिक अभ्यर्थी एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं में आवेदन करते हैं। लेकिन सेना में भर्ती हेतु समग्र व्यक्तित्व परीक्षण(कॉम्प्रेहेन्सिव पर्सनेल्टी टेस्ट) के कड़े मानको के कारण उनकी सफलता दर कम होती है। सेना और अर्द्धसैनिक बलों में राज्य के युवाओं का अधिकारी पद पर चयन प्रतिशत बढ़ाने के लिये उनको पहले से तैयार किया जाना जरूरी है। इसके लिये युवाओं का स्तरीय मानको के अनुरूप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम तथा साक्षात्कार प्रशिक्षण आयोजित किया जाना लाभप्रद होगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि वीरभूमि उत्तराखण्ड एक सैनिक बाहुल्य राज्य है और यहां के युवाओं में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। युवाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान कर एनडीए और सीडीएस परीक्षाओं में उनकी सफलता का प्रतिशत बढाया जा सकता है। इसके साथ ही इस प्रकार की व्यक्तित्व विकास की कार्यशालाएं सिर्फ सैन्य सेवाएं ही नही वरन अन्य सरकारी सेवाओं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी युवाओं के लिये लाभप्रद होगी।

बैठक में तय हुआ कि प्रथम चरण में कुमाऊं और गढ़वाल में प्रशिक्षण कार्याशालाएं(ट्रेनिंग वर्कशॉप) ऐसे स्कूल–कॉलेज के भवनों में संचालित होगी जहां पर्याप्त अवस्थापना सुविधाएं हो। ये कार्यशालाएं 02 से 03 सप्ताह की होगी जहां युवाओं को एनडीए और सीडीएस की चयन प्रक्रिया के अनुरूप व्यक्तित्व विकास, साक्षात्कार एवं अन्य शारीरिक परीक्षणों के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा। सैनिक कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग से समन्वय कर प्रशिक्षण कार्यशालाओं हेतु स्थायी केन्द्र के रूप में स्कूल या कॉलेज के भवन चयनित करेंगे जहां नियमित पठन–पाठन के साथ–साथ कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा सके।

मे.ज.भाकुनी के अनुसार पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने पर प्रति वर्ष दस हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। द्वितीय चरण में 11वीं–12वीं के छात्र–छात्राओं के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थायी मिलिट्री/सैनिक स्कूल खोलने पर भी विचार किया जा सकता है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग